एयर कंडीशनर गुणवत्ता आदेश के सख्त मानकों में ढील

नयी दिल्ली। सरकार ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के इरादे से एयर कंडीशनर (एसी) उद्योग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) से जुड़े मानकों में ढील दी है। एयर कंडीशनरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 2019 में क्यूसीओ आदेश जारी किया था और यह पिछले साल अक्टूबर से लागू हुआ है लेकिन इसके मानदंडों को लागू करने को लेकर एसी उद्योग के हितधारकों की तरफ से जताई जा रही मुश्किलों को देखते हुए इनमें ढील देने का फैसला किया गया है। आदेश के कारण उद्योग को होने वाली समस्याएं दूर करने के लिए सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने संशोधन पेश किए हैं। एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उपकरण और संबंधित कलपुर्जों के विनिर्माताओं को 7,000 वाट से अधिक क्षमता के हर्मेटिक कम्प्रेसर के लिए इस आदेश से एक साल की छूट दी गई है। इसके अलावा विनिर्माताओं की तरफ से शोध एवं विकास के लिए आयात किए जाने वाले 200 उत्पादों को भी साल भर में छूट मिलेगी। हालांकि, इन आयातित वस्तुओं को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इनका निपटान कबाड़ के रूप में किया जाना चाहिए।

अधिसूचना के मुताबिक, मूल उपकरण विनिर्माता ऐसे सामान या वस्तुओं का सालाना आधार पर रिकॉर्ड रखेंगे और यदि सरकार चाहे तो उसे उपलब्ध कराएंगे। डीपीआईआईटी ने पांच दिसंबर, 2019 को एयर कंडीशनर और उसके संबंधित कलपुर्जों, हर्मेटिक कम्प्रेसर और तापमान संवेदन नियंत्रण आदेश, 2019 जारी किया था। बाद में व्यावहारिक समस्याओं के चलते उद्योग के अनुरोध पर तापमान संवेदन नियंत्रणों को इस सूची से हटा दिया गया था।

सोने और चांदी में गिरावट

नयी दिल्ली। विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 230 रुपये टूटकर 63,970 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 64,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। इस दौरान चांदी भी 400 रुपये टूटकर 78,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 78,800 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी गिरावट के साथ क्रमश: 2,059 डॉलर प्रति औंस और 23.60 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार करते दिखे। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में जिंसों के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि डॉलर सूचकांक में मजबूती और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में तेज वृद्धि के बाद सोने की कीमतों पर दबाव रहा।

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट

मुंबई। स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और बीएसई सेंसेक्स 536 अंक और लुढ़क गया। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच मुख्य रूप से एचडीएफसी बैंक और आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार में गिरावट आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 535.88 अंक यानी 0.75 प्रतिशत की गिरावट के साथ 71,356.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 588.51 अंक तक लुढ़क गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 148.45 अंक यानी 0.69 प्रतिशत फिसलकर 21,517.35 अंक पर रहा। सेंसेक्स की कंपनियों में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेस्ले, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी बैंक और मारुति प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, आईटीसी, भारती एयरटेल और भारतीय स्टेट बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, नये संकेतकों के अभाव और शेयरों के मूल्यांकन को लेकर चिंता से निवेशक बाजार से दूर रहे। चीन और यूरो क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट के साथ वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेत से 2024 में वैश्विक आर्थिक पुनरुद्धार को लेकर चिंता बढ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण, बाजार को नीतिगत दर के बारे में संकेत को लेकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिर्जव की बैठक के बैठक के ब्योरे की प्रतीक्षा है। ब्योरा आज जारी होगा। महंगाई कम रहने के बावजूद कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में धीमी बढ़ोतरी की वजह से दिसंबर में देश के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि घटकर डेढ़ साल के निचले स्तर पर आ गई। बुधवार को जारी एक मासिक सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली है। एचएसबीसी इंडिया के विनिर्माण पीएमआई सर्वेक्षण से पता चलता है कि कारखाना ऑर्डर और उत्पादन में नरम वृद्धि हुई। हालांकि, आगामी वर्ष के लिए कारोबारी भरोसा मजबूत हुआ है। एसएंडपी ग्लोबल के मासिक सर्वेक्षण के अनुसार मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) दिसंबर, 2023 में घटकर 54.9 पर आ गया। यह इसका 18 माह का निचला स्तर है। नवंबर, 2023 में यह 56 के स्तर पर था। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट लाभ में रहा। यूरोप के बाजारों में शुरुआती कारोबार में नरम रुख रहा। अमेरिकी बाजार मंगलवार को नुकसान में रहा। इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंटक्रूड 0.55 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75.47 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 1,602.16 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे थे। सेंसेक्स मंगलवार को 379.46 अंक और निफ्टी 76.10 अंक के नुकसान में रहा था।

क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें बढ़ीं

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि क्रेडिट सूचना कंपनियों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों में बढ़ोतरी हुई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि केंद्रीय बैंक के पर्यवेक्षण मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना कंपनियों के आचरण को लेकर कुछ चिंताएं देखी गई हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे और कर्ज संबंधी सूचनाएं देने वाली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में उन विशिष्ट क्षेत्रों का भी जिक्र किया गया जहां सीआईसी को ध्यान देने की जरूरत है। बैठक के बाद जारी बयान के मुताबिक, स्वामीनाथन ने हाल में क्रेडिट जानकारी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने और रिजर्व बैंक के निरीक्षणात्मक मूल्यांकन के दौरान कुछ चिंताएं सामने आने की बात कही। स्वामीनाथन ने बैठक में कहा कि सीआईसी को ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निपटान करने, आंतरिक लोकपाल ढांचे को मजबूत करने, डेटा सुधार अनुरोधों के सुव्यवस्थित प्रबंधन के अलावा साइबर सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता को सशक्त करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान देने की जरूरत है। बयान के अनुसार, इस बैठक में आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग और विनियमन विभाग के कार्यकारी निदेशकों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

एनजीसी को तेल-गैस के सात ब्लाक, रिलायंस-बीपी के हिस्से में आया एक ब्लाक

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को तेल एवं गैस की खोज के लिए आयोजित नवीनतम बोली दौर में सात ब्लॉक मिले हैं जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी पीएलसी के गठजोड़ के हिस्से में एक ब्लॉक आया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि मुक्त क्षेत्र लाइसेंस नीति के आठवें दौर में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए 10 ब्लॉक की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि बोली में रखे गए सभी 10 ब्लॉक के अनुबंध पर बुधवार सुबह हस्ताक्षर किए गए। इन ब्लॉक में से ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) को सात जबकि रिलायंस-बीपी गठजोड़, ऑयल इंडिया लिमिटेड और सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को एक-एक ब्लॉक मिला है। इसके साथ कोल-बेड मीथेन (सीबीएम) के तीन ब्लॉक भी आवंटित किए गए और ओएएलपी का नौवां दौर बोली के लिए खोल दिया गया। एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया कि प्रतिबद्ध अन्वेषण कार्य कार्यक्रम के लिए दिए गए ब्लॉकों में 23.3 करोड़ डॉलर का निवेश होने का अनुमान है। भारत ने ओएएलपी के आठवें दौर में बोली लगाने के लिए जुलाई, 2022 में 10 ब्लॉक की पेशकश की थी। बोली की समय सीमा कुछ बार बढ़ाए जाने के बाद यह दौर जुलाई, 2023 में बंद हो गया था। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के मुताबिक, इन ब्लॉक के लिए पांच कंपनियों- ओएनजीसी, वेदांता लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल), सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस-बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड ने मिलकर 13 बोलियां लगाई थीं। प्रस्तावित 10 ब्लॉक में से सात को एकल बोलियां मिली थीं जबकि अन्य तीन ब्लॉक के लिए दो-दो बोलियां आई थीं। एक्सॉनमोबिल, शेवरॉन और टोटलएनर्जीज जैसे वैश्विक ऊर्जा दिग्गजों ने ने कोई बोली नहीं लगाई। डीजीएच के अनुसार, ओएनजीसी छह ब्लॉकों के लिए एकमात्र बोलीदाता थी जबकि कृष्णा गोदावरी बेसिन में अत्यंत गहरे समुद्र में स्थित ब्लॉक के लिए रिलायंस-बीपी एकमात्र बोलीदाता थी। कुल मिलाकर, ओएनजीसी ने 10 में से नौ ब्लॉक के लिए बोली लगाई और सात ब्लॉक हासिल करने में सफल रही। इसने सिर्फ उस ब्लॉक के लिए बोली नहीं लगाई जिसके लिए रिलायंस-बीपी ने दावेदारी पेश की थी। पुरी ने इन ब्लॉक आवंटन अनुबंधों पर हस्ताक्षर के समय कहा, च्चेल खोज एवं उत्पादन बढ़ाने और उसे मजबूत करने की दिशा में भारत की खोज में एक महत्वपूर्ण अवसर, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी यात्रा को काफी तेज करेगा। इसके साथ ही विशेष सीबीएम बोली दौर-2022 के तहत दिए गए तीन कोल-बेड मीथेन ब्लॉक के लिए भी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

इस साल आ रहे हैं दिग्गज कंपनियों के आईपीओ

नयी दिल्ली। भारत के प्राइमरी मार्केट के लिए 2024 काफी बिजी रहने वाला है। कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ इस साल मार्केट में लॉन्च होंगे। इस साल कंपनियां आईपीओ के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाने की तैयारी कर रही हैं। यह रकम साल 2023 में जुटाई गई 49,434 करोड़ रुपए की रकम से दोगुनी है। इन आईपीओ की एवरेज साइज भी दोगुने से अधिक 2000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। इस साल कई लार्ज साइज आइपीओ मार्केट में डेब्यू करने वाले हैं। 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाने जा रही करीब 28 कंपनियों को सेबी से आईपीओ के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, 36 अन्य कंपनियों ने सेबी के पास आईपीओ के लिए आवेदन किया हुआ है। प्राइमडेटाबेस डॉट कॉम के अनुसार, इन कंपनियों की 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाने की योजना है। इनमें ओला इलेक्ट्रिक भी शामिल है, जिसने पिछले महीने सेबी में डीआरएचपी फाइल किया था। इस तरह यह फ्रेश पब्लिक ऑफर लाने वाला पहला ईवी स्टार्टअप होगा। 8,300 करोड़ रुपए यानी 1 बिलियन डॉलर के इस आईपीओ में 5500 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे। वहीं, 95.2 मिलियन शेयर ओएफएस में रखे जाएंगे। सॉफ्टबैंक समर्थित फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने हाल ही में 1 अरब डॉलर के पब्लिक इश्यू के लिए बैंकर्स का चुनाव किया है। 2023 की आखिरी तिमाही में आईपीओ और ब्लॉक एक्टिविटी दोनों में ही तेजी देखने को मिली थी। यह ट्रेंड 2024 में भी जारी रहेगा। घरेलू और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का मजबूत निवेश इसे सपोर्ट करेगा। ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप बायजू भी अपने ट्यूशन बिजनस आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के आईपीओ के जरिए इस साल 1 अरब डॉलर की रकम जुटाना चाहता है।

मार्केट खुलते ही रॉकेट बने अडानी ग्रुप के शेयर

नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आज अडानी-हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाने वाला है। उससे पहले अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी तेजी देखी जा रही है। अडानी के शेयरों में 10 फीसदी तक तेजी आई है। ग्रुप की सभी दस लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में उछाल आई है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में सबसे ज्यादा 10 फीसदी उछाल आई है जबकि अडानी टोटल गैस में आठ फीसदी और एनडीटीवी में सात फीसदी तेजी आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी विल्मर, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पावर के शेयरों में पांच से छह फीसदी तेजी आई है। इसी तरह अडानी पोर्ट्स में तीन फीसदी तक तेजी दिख रही है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के बारे में एक विस्फोटक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत के साथ छेड़छाड़ समेत कई तरह के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट आज अडानी-हिंडनबर्ग मामले में फैसला सुनाने जा रहा है। कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज किया था लेकिन इससे ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। एक समय तो ग्रुप का मार्केट कैप आधे से भी कम रह गया था लेकिन हाल में इसमें सुधार आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को इस मामले की जांच करने को कहा था। सेबी ने अगस्त में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और फिर नवंबर में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

स्वामी ज्ञानमण्डल प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक ओमप्रकाश शुक्ला द्वारा आज यंत्रालय १, जापलिंग रोड, लखनऊ से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
शार्दूल विक्रम गुप्त

स्थानीय सम्पादक
हरिन्दर सिंह साहनी

वाराणसी : सन्त कबीर मार्ग, **गोरखपुर** : बैंक रोड, **इलाहाबाद** : 3, लीडर रोड, **कानपुर** : बासमंडी, **झांसी** : गांधी भवन के सामने, **आगरा** : महात्मा गांधी मार्ग, **बरेली** : परसा खेड़ा रोड नं. 3, **पटना** : फ्रेजर रोड, **रांची** : नामकुम इण्डस्ट्रियल एरिया, **जमशेदपुर**: कालीमाटी रोड

वर्ष-35 संख्या-12288

आर.एन.आई. नं. 47967/89
फोन-0522-2209312, 2209313

aaajlucknow@yahoo.com
aajlucknow@gmail.com

पी.आर.बी. अधिनियम के अन्तर्गत समाचार चयन के लिये स्थानीय सम्पादक जिम्मेदार होंगे तथा समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन होंगे।

ईवी पर घटेगा आयात शुल्क देसी उद्योग कर रहे विरोध

नयी दिल्ली। सरकार ने देसी वाहन कंपनियों को दोटूक बता दिया है कि भारत और ब्रिटेन के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर शुल्क में रियायत देनी ही होगी। मगर उद्योग को राहत देने के लिए वह सुनिश्चित करेगी कि ब्रिटिश ईवी कंपनियों को रियायत किस्तों में दी जाएगी, जिससे भारतीय बाजार में उनकी पैठ भी धीरे-धीरे बढ़े। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से उभरता हुआ बाजार है। इसे देखते हुए घरेलू वाहन निर्माताओं ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कटौती का पुरजोर विरोध किया है। इसीलिए सरकार इस समझौते के तहत चरणबद्ध तरीके से शुल्क घटाने की बात कह रही है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा, च्हम मानते हैं कि भारत में ईवी उद्योग की अभी शुरुआत ही हुई है। इसलिए हम इस बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोलने का उचित और सुरक्षित तरीका तलाश रहे हैं। ऐसा करते समय हम उद्योग की चिंताओं को जरूर ध्यान में रखेंगे।ज् उस व्यक्ति ने कहा, च्उद्योग कोसुरक्षित रखने और फलने-फूलने का मौका देने के लिए 5, 10 या 15 साल की जरूरत हो सकती है। इतना वक्त काफी होगा। अगर सरकार सीमित संख्या में वाहनों को कम शुल्क पर आयात करने की इजाजत देती है तो उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। उद्योग को यह बात समझनी होगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर फिलहाल भारी शुल्क लगता है। देश में 40,000 डॉलर यानी करीब 34 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली पूरी तरह असेंबल की गई इलेक्ट्रिक कारके आयात पर 100 फीसदी शुल्क वसूला जाता है। 40,000 डॉलर से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों के आयात पर 70 फीसदी शुल्क लगाया गया है। अधिक आयात शुल्क लगाए जाने के पीछे दलील यह दी जाती है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है।

अमेरिका पर बढ़ रहा कर्ज का बोझ

नयी दिल्ली। अमेरिका में संघीय सरकार का कुल राष्ट्रीय कर्ज 34,000 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया है। कर्ज के इस स्तर से पता चलता है कि आने वाले वर्षों में सरकार को देश के बही-खाते को सुधारने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। अमेरिकी वित्त विभाग ने मंगलवार को देश की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह राजनीतिक रूप से बंटे देश के लिए तनाव पैदा करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, बिना वार्षिक बजट के सरकार के कामकाज के कुछ हिस्सा ठप हो सकता है। रिपब्लिकन सांसदों और व्हाइट हाउस ने पिछले साल जून में देश की ऋण सीमा को अस्थायी रूप से हटाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे ऐतिहासिक चूक या च्डिफॉल्टज् का जोखिम टल गया था। यह समझौता जनवरी, 2025 तक चलेगा। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज कहीं अधिक तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस के बजट कार्यालय ने जनवरी, 2020 में वित्त वर्ष 2028-29 में सकल संघीय ऋण 34,000 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान लगाया था लेकिन 2020 में शुरू हुई कोविड महामारी की वजह से कर्ज इस स्तर पर अनुमान से कई साल पहले पहुंच गया है। राष्ट्रीय कर्ज का फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं दिख रहा है, क्योंकि निवेशक संघीय सरकार को कर्ज देने को तैयार हैं। यह कर्ज सरकार को कर बढ़ाए बिना कार्यक्रमों पर खर्च जारी रखने की अनुमति देता है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दशकों में कर्ज का यह रास्ता राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई बड़े कार्यक्रमों को जोखिम में डाल सकता है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड-अयोध्या

पत्रांकः- 1393/न.नि.ख.अयो./अधि0अभि0/ टेण्डर /2023-24/ दिनांक 27 दिसम्बर, 2023

अल्पकालीन निविदा संख्या-56/अधि0अभि0/2023-24

महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा 2100 नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (सामान्य/विशेष घटक) के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु मुहरबंद पृथक-पृथक अल्पकालीन निविदाएं उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से दिनांक 20.01.2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदाएं दिनांक 20.01.2024 को प्रातः 11.30 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड अयोध्या के कार्यालय में रखे गये निविदा बाक्स में डाली जा सकती हैं। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20.01.2024 को उपस्थित निविदादाताओं/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष अपराह्न 02.00 बजे से अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड अयोध्या के कार्यालय में खोली जायेंगी। निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के अनुपस्थित होने पर, निविदा खुलने के समय में कोई भी परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 10.01.2024 पूर्वाह्न 10.00 बजे से दिनांक 19.01.2024 को अपराह्न 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित मूल्य भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। कार्यों के सम्बन्ध मे विशेष शर्तें निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध करायी जायेंगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा (नग)	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य+ जी0एस0टी0 (रू0 में) + स्टेशनरी	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot No. 01	Supply and carriage of pea gravel 2.00mm to 3.35 mm size from Lalkuan to Dist. Ayodhya store of TWCD Ayodhya including cost of royalty, loading, unloading and stacking at store excluding G.S.T.	125 घन मीटर	9.43	19000.00	225.00 + GST (नियमानुसार) + 500.00	60 दिवस	"B" अथवा उच्च श्रेणी
Lot No. 02	Supply and carriage of pea gravel 2.00mm to 3.35 mm size from Lalkuan to Dist. Barabanki store of TWCD Ayodhya including cost of royalty, loading, unloading and stacking at store excluding G.S.T.	125 घन मीटर	8.90	18000.00	225.00 + GST (नियमानुसार) + 500.00	60 दिवस	"B" अथवा उच्च श्रेणी
Lot No. 03	Supply and carriage of pea gravel 2.00mm to 3.35 mm size from Lalkuan to Dist. Amethi store of TWCD Ayodhya including cost of royalty, loading, unloading and stacking at store excluding G.S.T.	125 घन मीटर	9.48	19000.00	225.00 + GST (नियमानुसार) + 500.00	60 दिवस	"B" अथवा उच्च श्रेणी
Lot No. 04	Supply and carriage of pea gravel 2.00mm to 3.35 mm size from Lalkuan to Dist. Sultanpur store of TWCD Ayodhya including cost of royalty, loading, unloading and stacking at store excluding G.S.T.	125 घन मीटर	9.47	19000.00	225.00 + GST (नियमानुसार) + 500.00	60 दिवस	"B" अथवा उच्च श्रेणी
Lot No. 05	Supply and carriage of pea gravel 2.00mm to 3.35 mm size from Lalkuan to Dist. Gonda store of TWCD Ayodhya including cost of royalty, loading, unloading and stacking at store excluding G.S.T.	125 घन मीटर	9.18	19000.00	225.00 + GST (नियमानुसार) + 500.00	60 दिवस	"B" अथवा उच्च श्रेणी

निविदा से सम्बंधित अधिक जानकारी अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड अयोध्या के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

उ0प्र0 200211 दिनांक-03.01.2024
www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है

अधिशासी अभियन्ता
नलकूप निर्माण खण्ड-अयोध्या

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता बहराइच-श्रावस्ती वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बहराइच

पत्रांक : 2491 /8काम/ई-टेण्डर/2023-24 दिनांक : 30.12.23

ई-निविदा सूचना

1. अधीक्षण अभियन्ता, बह0-श्राव0 वृत्त, लो0नि0वि0, बहराइच द्वारा महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग में 'ए' श्रेणी (मार्ग कार्य) के पंजीकृत निविदादाताओं से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से जनपद श्रावस्ती के निम्न वर्णन के अनुसार मार्ग निर्माण हेतु कार्य की निविदा आइटम दरों के आधार पर आमंत्रित की जाती है।

(विधानसभा-मिनगा)

क्र0 सं0	जनपद	कार्य का नाम	निविदा की लागत (बिना जी0एस0टी0) (रू0 लाख में)	निविदा की धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (समस्त करों सहित रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रावस्ती	वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद श्रावस्ती में खुर्शीद नाला से पूरे वाया खैरीकला मार्ग (अ0जि0मा0) मार्ग के चैनेज 0.000 से 7.000 तक (लम्बाई 7.00 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीसे बढाकर 7.00 मी0 में किया जाना) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	1800.00	30.00	(300+10000 +1854) =12154.00	12 Month

2. बिड डाक्यूमेन्ट की उपलब्धता एवं बिड-सबमिट करने का माध्यम-
   (क) बिड डाक्यूमेन्ट आन-लाईन दिनांक 06-01-2024 से 16-01-2024 तक उपलब्ध रहेगी, जो आन-लाइन http://etender.up.nic.in पर ही सबमिट किया जायेगा।
   (ख) निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेब-साइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। निविदायें आन-लाइन डालने हेतु निविदादाता के पास किसी डिजिटेल सिग्नेचर सार्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथोरिटी द्वारा जारी डिजिटेल सिग्नेचर सार्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
   (ग) ई-प्रोक्योरमेण्ट के माध्यम से निविदायें डालने की अन्तिम तिथि 16-01-2024 दोपहर 12:00 बजे तक एवं टेकनिकल क्वालिफिकेशन पार्ट-1 दिनांक 16-01-2024 अपराह्न 12:30 बजे से कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, बहराइच-श्रावस्ती वृत्त, लो0नि0वि0, बहराइच में खोला जायेगा। विस्तृत विवरण http://etender.up.nic.in देखा जा सकता है।
   (घ) निविदाता को निविदा प्रपत्र मूल्य एवं बिड सिक्योरिटी धनराशि up e-tender portal पर इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से आन लाइन जमा करना होगा।
   (ड) शासनादेश संख्या 14/2020/879/तेइस-7-2020-176(सा0)/06 दिनांक 25-08-2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही प्रहरी के माध्यम से की जायेगी।
   (च) सारणी में कालम-7 में अंकित कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह में वर्षा ऋतु सम्मिलित है।
   (छ) कार्य पूर्ण होने के पश्चात डिफेक्ट लाइविलिटी पीरियड 03 वर्ष का होगा।

(सर्वेश कुमार हरित)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
श्रावस्ती

(मलिखान)
अधीक्षण अभियन्ता
बहराइच-श्रावस्ती वृत्त, लो0नि0वि0,
बहराइच

उ0प्र0 200173 दिनांक-03.01.2024 www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है

सूचना

मैंने अपना नाम Usman Ashiqe Ali Ansari से बदलकर Usman Ali Ansari रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना और पहचाना जाए S/o Ashiqe Ali Ansari 14,Pakdi Nandlal Karahiya Gosai Siddharth Nagar U P 272193

सूचना

संजू पत्नी ओमप्रकाश और संजू देवी पत्नी ओमप्रकाश दोनों नाम एक ही महिला के हैं जो कि कस्बा टिकैतगंज मजरे मोहसंड फतेहपुर बाराबंकी निवासी है।प्रार्थिनी का डाकघर खाता संख्या 1876199935 व आधार नंबर 896268578843 है।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैने अपना नाम KARAN से बदलकर KARAN KASHYAP कर लिया है। अबसे मुझे KARAN KASHYAP नाम से जाना व पहचाना जाय। KARAN KASHYAP s/o HUSENI LAL गांव- जिगिनिया, पोस्ट- नन्दनगर, तहसील- हर्रैया, जिला- बस्ती (उ.प्र.)।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैने अपना नाम INDRAJEET से बदलकर INDRAJEET GUPTA कर लिया है। अबसे मुझे INDRAJEET GUPTA नाम से जाना व पहचाना जाय। INDRAJEET GUPTA S/o RAM AUTAR गांव- लक्ष्मनपुर, पोस्ट- सिकन्दरपुर, तहसील- हर्रैया, जिला- बस्ती (उ.प्र.)।

दैनिक मंडी समीक्षा

नयी दिल्ली। ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म होने के बाद लिवाली बढ़ने से काबली चने में 200-300 रुपए, मसूर में 50-100 रुपए, चना खड़ी मोटर राजस्थान तथा चना दाल में 100-100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई। बाजरा कैटलफीड में 30-40 रुपए, ज्वार में 50 रुपए तथा मक्की में 10-20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, लिवाली कमजोर पडने से बारीक चावल में 50-50 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी आई। तेल तिलहन बाजार में, लिवाली कमजोर ही बनी होने से सरसों एक्सपैलर में 100 रुपए, सरसों, चावल तेल पंजाब तथा बिनौला मिल डिलीवरी में 30-50 रुपए प्रति क्विंटल की मंदी आई। चीनी बाजार में, लिवाली बढ़ने से विभिन्न मिलों की चीनी में 10-60 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई। गुड़-शक्कर बाजार में लिवाली कमजोर पडने से गुड़ पेड़ी में 100 रुपए की मंदी आई। किराना बाजार में, स्टॉकिस्टों की लिवाली कमजोर ही बनी होने से जीरा सामान्य तथा मशीन क्लीन एक-एक हजार रुपए प्रति क्विंटल टूट गया। हल्दी ईरोड गट्ठा एज ईट इज तथा मिनी सेलम फली में 100-100 रुपए की मंदी दर्ज की गई। चिरौंजी में 50 रुपए, मगज तरबूज में 2-3 रुपए प्रति किलोग्राम की मंदी आई। कालीमिर्च में 10 रुपए, बड़ी इलायची में 20 रुपए, छोटी इलायची में 50-75 रुपए प्रति किलोग्राम की मंदी आई।